Decentralised Sanctioning of Power Projects

1406. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the action, if any, taken by any State Government under the plan announced to decentralise sanctioning of power projects at the State level;

(b) the names of those States; and

(c) the difficulties, if any faced by the Central Government or the State Governments in implementing this plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) State Governments are understood to have sanctioned schemes under the delegated powers, which are likely to provide benefits during the Ninth Plan. Since these schemes have been sanctioned by the State Governments, they fall within the purview of respective State Governments and are not being monitored on a regular basis by the Government of India. Further, as the ceiling limit for clearance of power projects through competitive bidding has been raised to Rs. 1000 crores recently, it would be difficult to make any assessment at this juncture. A review of these projects shall be taken up at an appropriate time.

Fuel for small Power Plants

1407. SHRI PREM CHAND GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are planning to provide fuel for the small power plants to be set up with a capacity of 30-50 MW, as short term solution to the power shortage; and

(b) if so, what is Government's policy in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) Yes, Sir.

(b) Detailed guidelines were issued to the concerned States for recommending projects including small power plants of the capacity of 30-50 MW, for naphtha/liquid fuel linkage within the capacity (in MW) allocated to respective states. States are making project-wise recommendations for provisional fuel linkage.

उत्तर प्रदेश में गलिबाहा विद्युत सब-स्टेशन की क्षमता

1408. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश के कुरेभार क्षेत्र में स्थापित गलिबाहा विद्युत सब-स्टेशन की विद्युत क्षमता कितनी है और उससे विद्युत की मांग कितनी है;

(ख) विद्युत की अत्यधिक मांग को देखते हुए क्या सरकार इस स्टेशन की क्षमता बढ़ाने अथवा एक नया सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है;

(ग) क्या सब-स्टेशन सायं 6.00 बजे से रात्रि को 10.00 बजे तक घरेलु बिजली (विद्युत) की आपूर्ति बन्द कर देता है जबकि इस समय के दौरान विद्युत की सर्वाधिक आवश्यकता होती है;

(घ) यदि हां, तो स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) जिला प्रशासन द्वारा जारी आपूर्ति की वर्तमान समय-सारणी क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सुलतानपुर के कुरेभार क्षेत्र में गलिबाहा विद्युत उप-केन्द्र की क्षमता 3 एम०वी०ए० जबकि वर्तमान में मांग 160 एम्पियर (अथवा 3.52 एम०वी०ए०) है।

(ख) भार-मांग में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने कुरेभार उप-केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ऊपर (ख) में यथा उल्लिखित, भार-मांग में वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने उप-केन्द्र की क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव किया है।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जिलावार विद्युत के वितरण की वर्तमान समय-सारणी संलग्न है।